two sub-groups i.e. Joint Planning Group and Joint Action Group. The sub-groups have identified and prioritised the strategic systems with a view to boosting the self-reliance.

सेना में हरिजनों और अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती

4161. **श्री नागमणि:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को कमजोर समझकर उन्हें सेना में आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सेना में उनका आरक्षण करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) और (ख) सेना में भर्ती जाति, पंथ या धर्म का विचार किए बिना समाज के सभी वर्गों के लिए खुली है बशर्ते कि वे निर्धारित किए गए शारीरिक, चिकित्सीय और शैक्षिक मानदंड पूरे करते हों।

(ग) संक्रियात्मक दक्षता का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए रक्षा सेनाओं में नियुक्तियां और चयन पूर्णत: मैरिट के आधार पर किए जाते हैं और जाति, समुदाय, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है।

Delay in Procurement of AJT Aircraft

4162. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem whcih appeared in the Tribune dated 24th April, 1997 regarding urgency of induction of Advanced Jet Trainer;

(b) whether it is a fact that Standing Committee on Defence has in its recent report to parliament, criticised Government for delay in acquiring Advanced Jet Trainers even though the requirement thereof was felt long back in 1984; and

(c) the reasons for delaying the decision and whether Government have reviewed its decision; if so, by when the AJTs would be procured?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) The commercial negotiations with the shortlisted vendors are in progress. The acquisition of AJT has been projected in the 9th Plan.

गुजरता में रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना

4163. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्यों में स्थापित किये जा रहे रक्षा उत्पादन संबंधी एककों के संबंध में नीति, क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात भी इन अपेक्षित राज्यों में से एक है और आजादी के 50 वर्षों बाद भी राज्य में कोई भी बड़ा एकक स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) क्या राज्य की विपुल संपत्ति की घोर अवहेलना की जा रही है तथा सरकार कुछ राज्यों को ही महत्व दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात के संबंध में रक्षा मंत्रालय का दृष्टिकोण क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) से (ङ) एक नए रक्षा उत्पादन यूनिट को स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार करने पर भू-सामरिक, तकनीकी आर्थिक और प्रशासनिक विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सरकारी नीति के अनुसार उसके वास्ते स्थान का चयन किया जाता है। प्रस्तावित नए यूनिट के स्थान के लिए राज्यों का चयन करने के वास्ते लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा नई परियोजनाओं के लिए स्थानों के चयन पर जारी किए गए दिशानिर्देशों को भी सरकार ध्यान में रखती है। उसके बाद नई यूनिटों की परिहार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन चुने हुए राज्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्रस्तावित

यूनिट के लिए स्थान बताएं। राज्य सरकारों द्वारा बताए गए स्थानों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित स्थल चयन समिति द्वारा की जाती है, समिति की सिफारिशें पर्यावरण और वन मंत्रालय को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दी जाती हैं। तत्पश्चात् सरकार किसी विशिष्ट स्थान पर यूनिट स्थापित करने का निर्णय लेती है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का प्रश्न नहीं उठता।

3. उड़ीसा में आयुध निर्माणी बोलंगीर को पूरा करने के अलावा पिछले लगभग 10 वर्षों में किसी यूनिट की स्थापना को स्वीकृति नहीं दी गई है। पहले से ही उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देश के किसी भी भाग में किसी नई रक्षा उत्पादन यूनिट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों का उपलब्ध कराया जाना

4164. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सैनिकों को हथियार चलाने संबंधी अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद नहीं मिलता है और एक महीने में मुश्किल से दो बार ही युद्धाभ्यास हो पाता है; और

(ख) नई तोपों और अत्याधुनिक हथियारों से युद्धाभ्यास करने के संबंध में क्या नीतियां हैं तथा क्या यह युद्धाभ्यास किसी अंतराल पर कराया जाता है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) जी, नहीं।

(ख) गोलीबारी के अभ्यास की आवृत्ति यूनिटों के पास उपलब्ध हथियारों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

मृतक ग्रेफ (जी०आर०ई०एफ०) कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान

4165. श्री **गोविन्दराम मिरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रेफ ((जी०आर०ई०एफ०) के उन अधिकारियों या कर्मचारियों के परिवारों/आश्रितों को अनुग्रह धनराशि और अन्य मुआवजे दिये जाते हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान उग्रवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996 में ऐसे कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की इस प्रकार मृत्यु हुई और उन्हें पहले ही दिए गए या दिए जाने वाले मुआवजों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) और (ख) ग्रेफ (जी०आर०ई०एफ०) के कर्मचारी और अधिकारी, सामान्य देय राशि व ग्रेफ हितकारी निधि एवं सीमा सड़क विशेष राहत निधि तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुग्रह अनुदानों के साथ ही उदारीकृत पेंशन अवार्ड अथवा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजा, इनमें से जो भी अधिक हो, पाने के पात्र हैं।

(ग) वर्ष 1996 में तीन कार्मिक मारे गए थे और उन्हें देय राहतों का संवितरण दिया जा रहा है।

Installation of Composite Sonar Control System

4166. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the reasons for not taking any decision on the installation of Composite Sonar Control System developed at a high cost of Rs. 20 crore on the submarines;

(b) whether responsibility is proposed to be fixed on the officers concerned for inordinate delay; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) The Composite Sonar & Tactical Weapon Control System called 'PANCHENDRIYA', developed by Defence Research & Development Organisatin (DRDO), has already been installed on-board a submarine. Sea evaluation of the system will be completed by end 1997 after